(b) to (d) Ministry of Irrigation and the Central Water Commission have prepared an outline plan for National perspective of water resources development. The perspective envisages creation of storages at suitable sites on the various rivers where surpluses may be available and mass inter-basin transfer of waters to the needy areas. The perspective has two components, the Himalayan river development component for which cooperation of Neighbouring Countries will be required and the Peninsular development. The perspective is expected to increase the irrigation potential of the country by about 25 million ha. through surface water and about 10 million ha. through ground water and is expected to generate about 4,000 M. W. of hydro-power. The peninsular development component of the project has been taken up for investigation.

गाँवों में किसानों को उचित दर दुकानों से चीनी न मिलना

1206. **श्री छांगुर राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गांवों में किसानों को उचित दर दुकानों से चीनी नहीं मिल पाती है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में इन उचित दर दुकानों से क्या-क्या वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ग) किसानों को ये सभी वस्तुएं उचित दरों पर और समय पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरे देश में कार्य कर रही है और विभिन्न राज्यों से मिली सूचना से पता चलता है कि आबादी के सभी वर्गों, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी शामिल है, की जरूरतों को पूरा करने में यह प्रणाली आमतौर पर अच्छी तरह कार्य कर रही है। केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए साफ्ट कोक और नियंत्रित कपड़े के अलावा गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तुएं सप्लायी कर रही है। एक बार जब इन वस्तुओं की सप्लाई राज्य सरकारों को मिल जाती है तब यह उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वे आबादी के सभी वर्गों, जिसमें किसान भी शामिल हैं, को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण करने के लिए विभिन्न शहरों तथा राजस्व जिलों में इन वस्तुओं का आगे वितरण करें। सरकार ने पहले ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दी जाने वाली वस्तुएं पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर वास्तविक उपभोक्ताओं, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग भी शामिल हैं, को ही मिलें। इस संबंध में, राज्य सरकारों पर इस बात के लिए भी बल दिया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं की मात्रा उठाने, उनकी ढुलाई, भण्डारण और वितरण में उपयुक्त समन्वय स्थापित करें।

Sports Promotion in J & K

1207. PROF. SAIFUDDIN SOZ : Will the Minister of SPORTS be pleased to state :

(a) whether Union Ministry of Sports has schemes to promote sports in different parts of India; and

(b) if so, what measures are envisaged to promote sports in J & K especially when indoor sports complex has also been built by the J & K State ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS (SHRI ASHOK GEHLOT) : (a) and (b) Central assistance, including financial assistance for promotion of sports is made available to State Governments. The advantages of such assistance for the promotion of sports are at much admissible to Jammu & Kashmir as so other States.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उप अभियन्ता

1208. **श्री टी० एम० सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ग्रेड I से ग्रेड III में उप-अभियन्ता के पद पर काम कर रहे अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) उनमें अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ग) एसे उप-अभियन्ताओं की संख्या क्या है, जिनको "रोस्टर प्वांइन्ट" के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति की गई है; और

(घ) यदि किसी व्यक्ति की पदोन्नति रोक ली गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उप इन्जीनियर ग्रेड-I,II, III पदनाम वाले कोई पद नहीं हैं ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Projects Sanctioned Under RLEGP

1209. SHRI P. K. KODIYAN : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) how many projects under the Rural Landless Employment Guarantee Programme have been sanctioned by the Centre so far;

(b) the total funds sanctioned for each of these projects; and

(c) initial progress made by these projects ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI HARINATHA MISRA) (a) and (c) Upto 24-1-1984, 89 projects have been sanctioned by the Government under the Rural Landless Employment Guarantee Programme. These projects have been sanctioned recently and are in the initial stages of implementation.

(d) The details are given in the Annexure laid on the table of the House. Placed in Library (See No. LT 7870/84)

Enlarging Areas Under Cultivation of Oilseeds.

1210. SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL :
SHRIMATI USHA PRAKASH CHOUDHARI :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring larger areas under cultivation of oilseeds and strengthen and subsidise the same;

(b) whether Government also propose to provide protection to oilseeds crops grown by small farmers and cover the same under an insurance scheme;

(c) whether the seminar organised by National Productivity Council made important recommendations in this regard; and

(d) if so, the details thereof and the reaction of Government thereon ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The oilseed crops grown by small and marginal farmers are *inter alia* covered under the present scheme of crop insurance which is being implemented by the General Insurance Corporation of India (GIC) in collaboration with the State Governments. As per information received from GIC, oilseed crop like groundnut has been covered during Kharif 1983-84 season in the States of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra.

(c) Yes, Sir.

(d) The recommendation is that Government of India should consider to provide insurance cover for the oilseeds crops. The position with regard to Government reaction on this recommendation, has been indicated above at (b) of the reply.

पूर्वी चम्पारन, बिहार में मत्स्य-पालन

1211. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पूर्वी चम्पारण जिलों में इस प्रकार के 21 तालाबों, झीलों और छोटी नदियों की संख्या कितनी है जहाँ बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन कुछ किया जा सकता है और लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है तभी उससे देश की प्रोटीन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;